

# विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) के विकास की योजना आदिम जनजातीय समूह

अनुसूचित जनजातियों में, कुछ ऐसे आदिवासी समुदाय हैं, जिनकी जनसंख्या में कमी या स्थिरता है, साक्षरता का निम्न स्तर, तकनीक का पूर्व-कृषि स्तर और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 75 ऐसे समूहों की पहचान की गई है और उन्हें आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की सूची PTGs अनुलग्नक में है। इनमें से अधिकांश समूह संख्या में छोटे हैं, उन्होंने सामाजिक और आर्थिक प्रगति के किसी भी महत्वपूर्ण स्तर को प्राप्त नहीं किया है और आमतौर पर दूरदराज के इलाकों में गरीब बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सहायता प्राप्त करते हैं। इसलिए, वे अनुसूचित जनजातियों के बीच सबसे कमजोर वर्ग बन जाते हैं और उनकी सुरक्षा और उनकी विकास की घटती प्रवृत्ति की जाँच के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोण से हमारे देश में कुछ MADA nd ऐसी सूक्ष्म परियोजनाओं को मजबूत किया जा सकता है।

## उद्देश्य

चूंकि पीटीजी आदिवासियों के बीच सबसे कमजोर वर्ग है और छोटे और बिखरे हुए आवास / निवास में पृथक, दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में निवास

करते हैं, इस योजना का उद्देश्य आवास विकास के दृष्टिकोण को अपनाने और सभी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके उनके सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना बनाना है। उनका सामाजिक और आर्थिक जीवन, ताकि पीटीजी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और एक प्रभाव दिखाई दे।

## क्षेत्र

यह योजना केवल 75 चिन्हित आदिम जनजातीय समूहों को कवर करेगी। यह योजना बेहद लचीली है क्योंकि यह प्रत्येक राज्य को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जो उनके पीटीजी और उनके सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के लिए प्रासंगिक हैं। इसके अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, मवेशी विकास, संपर्क मार्गों का निर्माण, प्रकाश उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों की स्थापना, जनश्री बीमा योजना सहित सामाजिक सुरक्षा या कोई अन्य नवीन गतिविधि शामिल हो सकती है। पीटीजी के व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास दृष्टिकोण, विशेष रूप से पीटीजी के लिए जो प्रकृति में खानाबदोश हैं। खानाबदोश पीटीजी को जीवन के व्यवस्थित मोड में लाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इस पर ध्यान से ध्यान दिया जाएगा। इस योजना के तहत धन केवल उन वस्तुओं / गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जो पीटीजी के अस्तित्व, संरक्षण और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें विशेष रूप से राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना या दिशानिर्देशों का उपयोग करके नियंत्रित नहीं किया जाता है जनजातीय उप-योजना और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत

विशेष केंद्रीय सहायता के तहत धन। धन और अधिकारियों के अभिसरण का सामान्य सिद्धांत लागू होगा।